



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 2004/कार्तिक 17, 1926

No. 263]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 2004/KARTIKA 17, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2004

फा. सं. 16-53/2003-डीडी-3.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 30 में यह व्यवस्था है :—

30. पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकारें अधिसूचना द्वारा, एक व्यापक शिक्षा स्कीम तैयार करेगी, जिसमें कि निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा:—

- (क) विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधाएं या इसके विकल्प के रूप में माताओं-पिताओं या अभिभावकों को वित्तीय सहायता जिसके कि वे अपने विकलांग बच्चों को स्कूल भेज सकें;
- (ख) स्कूलों, कालेजों या अन्य व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थाओं से वास्तु शिल्पीय बाधाओं को हटाना;
- (ग) स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां और अन्य सामग्री उपलब्ध कराना;
- (घ) विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- (ङ) विकलांग बच्चों के स्थापन के संबंध में माताओं पिताओं की शिकायतें दूर करने के लिए उचित मंच स्थापित करना;
- (च) दृष्टिहीन छात्रों तथा न्यून दृष्टि वाले छात्रों के लाभ के लिए पूर्णतया गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति में उपयुक्त संशोधन करना;
- (छ) विकलांग बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यचर्या को पुनः बनाना और
- (ज) श्रवण विकलांगता वाले छात्रों के लाभ के लिए पाठ्यचर्याओं को पुनः बनाना जिससे कि वे अपने पाठ्यचर्या के भाग के रूप में केवल एक भाषा लेने की उन्हें सुविधा हो।

2. दिसम्बर, 2002 में यथा संशोधित भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। तदनुसार भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का एक व्यापक तथा समेकित राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में "शून्य अस्वीकृत नीति" अपनायी गयी है जिससे कि कोई बच्चा इस शिक्षा पद्धति से वंचित न रहे। इस कार्यक्रम विशेष जरूरतमंद बच्चों सहित सभी बच्चों को आठ वर्षीय क्वालिटी शिक्षा मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया है। यह विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकल्पों और नीतियों का भी समर्थन करता है। भारत सरकार विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (आई.ई.डी.सी.) कार्यान्वित कर रही हैं। इस योजना में सामान्य स्कूलों में माइल्ड एवं मॉडरेट स्वरूप की विकलांगता वाले बच्चों को समेकित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आई ई डी सी योजना के अंतर्गत, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री वर्दी, अनुदेशक सामग्री, सहायक उपस्कर, दृष्टिहीनों के लिए पाठक सुविधाएं, अस्थि विकलांगों के लिए सहचर सुविधा, विशेष शिक्षक सुविधा, स्कूल परिसर में स्थित विकलांग बच्चों के लिए होस्टल सुविधा स्कूलों आदि में वास्तु शिल्पिय बाधा हटाने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. सरकार के संगठनों/स्वायत्त निकायों द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों को एक की स्थान पर लाकर इस अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से, निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

(क) विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधा अथवा इसके विकल्प के रूप में माताओं - पिताओं या अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जिससे कि विकलांग बच्चे भी स्कूलों में जा सकेंगे।

- (i) अपने बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करने वाले स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग बच्चे की जरूरतों के अनुरूप उपयुक्त परिवहन सुविधा प्राप्त करें। इसका मतलब होगा सुविधाओं की उपलब्धता जिससे कि पहियादार कुर्सी उपयोग करने वाले परिवहन तक पहुंच सकें और सेवाओं का उपयोग करने के लिए अन्य विकलांगताग्रस्त बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकें;
- (ii) वे स्कूल जो अपने बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं उनके स्कूलों में अध्ययनरत विकलांग बच्चों की जरूरत के अनुरूप परिवहन वाहन किराए पर/की व्यवस्था करके एक पद्धति स्थापित करनी चाहिए; और
- (iii) यदि विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधा की व्यवस्था करना संभव न हो तो विकलांगता वाले बच्चों के लिए माताओं, पिताओं के एक संघ स्वसहायता समूह, नागरिक कल्याण समूह बनाकर विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा सकते हैं।

(iv) सरकार की कुछ विद्यमान स्कीमों में विकलांग बच्चों हेतु परिवहन की व्यवस्था करने के एक घटक का प्रावधान है। इनका उपयोग किया जाना चाहिए।

(ख) स्कूलों, कालेजों या रोजगार परक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अन्य संस्थानों से वास्तुशिल्पीय बाधाओं को हटाना

(i) निर्मित की जा रही सभी नई स्कूल बिल्डिंगों में रैम्पस्, हैन्डरेलस और अन्य सुविधाएं जैसी बाधा मुक्त विशेषताएं होनी चाहिए जैसी कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), शहरी कार्य और राजेगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित की गई है। ये दिशा-निर्देश निर्मित वातावरण में बाधा-मुक्त पहुंच के लिए मानक निर्दिष्ट करते हैं।

(ii) सभी विद्यमान स्कूलों को भी अपनी स्कूल बिल्डिंगों में इस तरह परिवर्तन करना चाहिए कि ये बिल्डिंग बाधा-मुक्त हो जाएं।

(iii) रैम्पस की व्यवस्था सहित बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और उस क्षेत्र में उपयुक्त व उपलब्ध समुचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

(iv) संरचनात्मक डिजाइनिंग/परिवर्तन, योग्य सिविल इंजीनियर के निर्देशन में किया जाना चाहिए।

(v) एस.एस.ए., आई.ई.डी.सी. इत्यादि सहित विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों में उपलब्ध निधियों का इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(ग) स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों के लिए पुस्तकें, वर्दी और अन्य सामग्री प्रदान करना

(i) विकलांग बच्चों को स्कूल नियमित तौर पर उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जानी चाहिए।

(ii) आइ.ई.डी.सी. स्कीम में प्रत्येक विकलांग बच्चे को पुस्तकें और स्टेशनरी पर होने वाले व्यय के लिए 400 रुपए का सालाना सहायता अनुदान देने के प्रावधान का उल्लेख है। इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

(iii) यदि अन्य बच्चों को वर्दियां और अन्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है, तो विकलांग बच्चों को भी ये प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) विकलांग बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान की जानी चाहिए जैसे (क) दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल पुस्तकें बोलने वाली (टॉकिंग) पुस्तकें, गणित किट, विज्ञान किट, संवेदी प्रशिक्षण किट, चलने-फिरने (मोबिलिटी) के लिए बेंत, पाठ्य-वाक्(टेक्सट टू स्पीच) साफ्टवेयर और ब्रेल की बोर्ड वाला कम्प्यूटर हार्डवेयर इत्यादि (ख) श्रवण विकलांग बच्चों को - क्लीनिकल श्रव्यतामापी (ऑडियो मीटर), पोर्टेबल ऑडियोमीटर, वाक् और श्रवण विकलांग बच्चों के लिए इयर मोल्ड मेंकिंग का सूक्ष्ममापी यंत्र (माइक्रोमीटर), वाणी पहचान साफ्टवेयर और अन्य संगत उपस्कर।

(घ) विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

(i) विकलांग बच्चों को मेरिट के आधार पर शिक्षा-खर्च के वित्त पोषण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(ii) विकलांग छात्रों को सीधे ही मुद्रा के रूप में छात्रवृत्ति या स्कूलों को किए गए खर्च के रूप में सहायता दी जानी चाहिए।

(iii) विकलांग बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति की सूची का अलग से उल्लेख किया जाए और इस पर अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाए।

(iv) छात्रवृत्ति-प्राप्तकर्ताओं की सूची नियमित तौर से संशोधित की जाए।

(ङ) विकलांग बच्चों के नियोजन के संबंध में इनके अभिभावकों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त मंच स्थापित करना

(i) विकलांग बच्चों के अभिभावकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रत्येक स्कूल में अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन स्थापित की जानी चाहिए।

(ii) अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन की नियमित बैठकें होनी सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

(iii) विशेष जरूरत वाले बच्चों के माता-पिता की शिकायतों को दूर करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए एस एस ए के तहत गठित स्कूल प्रबंधन समितियां और ग्रामीण शिक्षा समितियों का उपयोग किया जाना चाहिए ।

(iv) कालेजों को भी इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(च) दृष्टिहीन छात्रों और कम दृष्टि वाले छात्रों के लाभ के लिए पूर्ण गणित प्रश्नों को समाप्त करने के लिए परीक्षा पद्धति में उपयुक्त संशोधन ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) ने परीक्षाओं में विकलांग बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । सी बी एस ई द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

(i) माध्यमिक स्कूल परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान में दृष्टि इनपुट पर आधारित विशेष कौशल की अपेक्षा वाले प्रश्नों के बदले वैकल्पिक प्रश्न दिए जा रहे हैं ।

(ii) दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक छात्रों को लिपिक का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है । लिपिक को उस कक्षा से एक कक्षा नीचे का छात्र होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है ।

(iii) दिल्ली के दृष्टि विकलांग छात्रों (कम दृष्टि वाले) को बड़े छापे वाले प्रश्न पत्र दिए जाते हैं ।

(iv) विकलांग छात्रों को वाह्य परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए एक घंटा अतिरिक्त दिया जाता है ।

(v) तीसरी भाषा में परीक्षा देने की छूट दी जाती है ।

3365 95/2004-2

(vi) इन छात्रों को जहां तक संभव हो भूतल पर परीक्षा दिलाने की व्यवस्था करने हेतु केन्द्र अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं ।

(vii) शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष रूप से अपनी श्रेणी को दर्शाना है और यह भी उल्लेख करना है कि उन्हें मुख्य उत्तर पुस्तिका में प्रदान किए गए कालम में लेखक प्रदान किया गया है ।

विकलांग बच्चों को सी बी एस ई द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के अतिरिक्त, दृष्टिहीन छात्रों और कम दृष्टि वाले छात्रों के लाभ के लिए मूल गणितीय प्रश्नों को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए ।

(छ) विकलांग बच्चों के लाभार्थ पाठ्यक्रम की पुनः संरचना

सम्मिलित शिक्षा पर विशेष बल है और इसलिए, बाल केन्द्रित अध्यापन पर बल दिया जाना चाहिए । विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का समुचित रूप से विकास विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाना चाहिए ताकि, ये बच्चे नियमित कक्षा में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें । पाठ्यक्रम का समुचित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि सी.बी.एस.ई. द्वारा विकलांग बच्चों के लिए की गई है । किए गए संशोधन निम्नलिखित हैं :-

विकलांग बच्चों (डिस्लेक्सिक, दृष्टिहीन स्पास्टिक और दृष्टि विकलांगता वाले उम्मीदवार) के पास दो भाषा के बजाए एक अनिवार्य भाषा का अध्ययन करने का विकल्प है । उनके द्वारा चयनित भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित तीन भाषा सूत्र की समग्र भावना के अनुरूप होनी चाहिए । एक भाषा के अतिरिक्त, वे निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं चार का चयन कर सकते हैं :

गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज विज्ञान, दूसरी भाषा, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान और प्रारंभिक सूचना प्रौद्योगिकी ।

(ज) श्रवण विकलांगताग्रस्त छात्रों के लाभ के लिए उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक भाषा लेना सुसाध्य बनाने हेतु पाठ्यक्रम का पुनः निर्माण ।

शिक्षा बोर्ड को अपने पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में केवल एक भाषा विकल्प प्रदान करते हुए श्रवण विकलांग बच्चों की शिक्षा आसान बनाने के लिए अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिए ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा संबंधी विषय - वस्तु की देखरेख करने वाले सरकार और इसके संगठन, अधिनियम की धारा 30 में उल्लिखित सुविधाओं को शामिल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे ताकि सभी बाधाएं और अवरोध दूर हों तथा विकलांग बच्चे अन्य बच्चों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों ।

श्रीमती जयति चन्द्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2004

F. No. 16-53/2003-DD.III—Section 30 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 stipulates the following :—

“30. Without prejudice to the foregoing provisions, the appropriate Governments shall by notification prepare a comprehensive education scheme which shall make provision for-

- (a) transport facilities to the children with disabilities or in the alternative financial incentives to parents or guardians to enable their children with disabilities to attend schools;
- (b) the removal of architectural barriers from schools, colleges or other institution imparting vocational and professional training .
- (c) the supply of books, uniforms and other materials to children with disabilities attending school;
- (d) the grant of scholarships to students with disabilities
- (e) setting up of appropriate fora for the redressal of grievances of parents regarding the placement of their children with disabilities;
- (f) suitable modification in the examination system to eliminate purely mathematical questions for the benefit of blind students and students with low vision;
- (g) restructuring of curriculum for the benefit of children with disabilities; restructuring the curriculum for benefit of students with hearing impairment to facilitate them to take only one language as part of their curriculum.”

2. The Constitution of India as amended in December, 2002 provides that free and compulsory education is a fundamental right of all children in the age group of 6-14 years.

Accordingly, the Ministry of Human Resources Development in the Government of India has formulated a comprehensive and integrated national programme of Sarv Shiksha Abhiyaan (SSA) to provide assistance to states. This programme adopts a 'zero-rejection policy' so that no child is left out of the education system. The programme has been launched to provide eight years of quality education to all children including children with special needs. It also supports a wide range of approaches, options and strategies for education of children with disabilities. The Government of India has been implementing a centrally sponsored scheme of Integrated Education for the Disabled Children (IEDC) in various States and UTs. The scheme endeavours to achieve the integration of children with disabilities of mild to moderate nature in normal schools. Under the Scheme of IEDC, 100% financial assistance is provided for transport facilities, books and stationery, uniform, instructional material, assistive equipments, readers facilities for the visually handicapped, attendant facility for the orthopaedically handicapped, special teacher facility, hostel facility for disabled children situated on school campus, removal of architectural barriers in schools etc.

3. In order to effectively implement provisions of Section 30 of the Act through convergence of various schemes/activities by the Government organizations/autonomous bodies, the following guidelines are issued:

- (a) Transport facility to the children with disability or in the alternative financial incentives to parents or guardians to enable their children with disabilities to attend schools;
 - (i) The schools providing transport facilities to their children should ensure that the children with disabilities also get the facility of transport suitable to their requirements. This would mean availability of facilities so that wheel-chair users have access to the transport and the children with other disabilities provided necessary assistance to utilize the services.
 - (ii) The schools, which are not providing transport facility to their children, should establish a system by hiring/arranging transport vehicles to suit the requirement of children with disabilities studying in their schools.
 - (iii) In case it is not possible to arrange for the transport facility for the children with disabilities, necessary arrangements may be made with the

help of the parents of the children with disabilities through formation of an association, self-help groups, citizen welfare groups.

Some of the existing schemes of the Government provide for a component for arranging transport for children with disabilities. These should be utilized.

- (b) Removal of architectural barriers from schools, colleges or other institutions imparting vocational and professional training.
- (i) All new school buildings being constructed should provide for barrier-free features such as ramps, handrails and other facilities as laid down in the guidelines for disabled and elderly persons issued by Central Public Works Department (CPWD) in the Ministry of Urban Affairs and Employment, Government of India. These guidelines set out standards for providing barrier-free access in built environment.
 - (ii) All the existing schools should also modify their school buildings in such a manner that they become barrier-free.
 - (iii) The creation of barrier-free environment including provision of ramps etc. should be done using locally available material and appropriate technology suitable and available in the area.
 - (iv) The structural designing/modification should be done under the guidance of qualified civil engineers.
 - (v) The funds available in various programmes/schemes including SSA, IEDC etc. should be utilized for the purpose.
- (c) Supply of books, uniforms and other materials to children with disabilities attending school.
- (i) To encourage children with disabilities to attend schools regularly, they should be provided with free text books.
 - (ii) The IEDC scheme has a provision for grant-in-aid for incurring expenditure on books and stationery upto Rs.400/- per annum per child with disabilities. This should be utilized.

- (iii) Children with disabilities should also be provided with uniforms and other materials, if these are provided to other children free of cost.
 - (iv) The children with disabilities should be provided with teaching/learning aids such as (i) for visually disabled children- Braille books, talking books, mathematics kits, science kits, sensory training kits, canes for mobility, text-to speech software and computer hardware having Braille key board etc (ii) for hearing disabled- clinical audio meter, portable audio meter, speech trainer, micrometer for ear-mold making for speech and hearing impaired, speech recognition software and other relevant equipments.
- (d) Grant of scholarships to students with disabilities.
- (i) Scholarships to fund the cost of education are provided to children with disabilities on the basis of merit.
 - (ii) Scholarships may be given in monetary form to students with disabilities directly or to the schools as underwritten cost.
 - (iii) List of students with disabilities being provided with scholarship should be separately mentioned and discussed in the Parent Teacher Association meetings.
 - (iv) List of scholarship-holders should be regularly revised.
- (e) Setting up of appropriate fora for the redressal of grievances of parents regarding the placement of their children with disabilities.
- (i) Parent Teacher association should be established in every school to redress the grievances of parents of children with disabilities.
 - (ii) Regular meetings of Parent Teacher Association should be ensured.
 - (iii) The school management committees and village education committees set up under SSA should be utilized to provide a forum to address grievances of the parents of children with special needs.
 - (iv) The colleges also should make similar arrangements.

- (f) Suitable modification in the examination system to eliminate purely mathematical questions for the benefit of blind students and students with low vision.

The Central Board of Secondary Education (CBSE) has taken a number of steps to provide facilities to the children with disabilities in examinations. Some of the major steps taken by CBSE are mentioned below:

- (i) Alternate questions in lieu of questions requiring special skills based on visual inputs are being provided in Mathematics and Science for Sec. School Examination (Class X).
- (ii) Blind, Physically Handicapped and Dyslexic Students are permitted to use an amanuensis. The amanuensis must be a student of a class lower than the one for which the candidate is taking the examination.
- (iii) The visually handicapped students (with low vision) appearing from Delhi are provided Questions Papers with enlarged print.
- (iv) Disabled candidates are allowed additional one hour (60 minutes) for each paper of external examination.
- (v) Exemption is granted from examination in the Third Language.
- (vi) Centre Superintendents have been instructed to make arrangements for the conduct of the examination of such candidates on the Ground Floor as far as possible.
- (vii) Physically challenged children are to specifically indicate their category and also state whether they have been provided with a writer in the columns provided in the Main Answer Book.

In addition to above facilities extended by CBSE to children with disabilities, there should be an effort to eliminate purely mathematical questions for the benefit of blind students and students with low vision.

- (g) Restructuring of curriculum for the benefit of children with disabilities

There is a focus on inclusive education and hence child centered pedagogy emphasized. The curriculum to meet the needs of children with disabilities

should be suitably developed in consultation with experts so that these children can learn together with other children in regular classrooms. There may be need to suitably modify the curriculum as done by CBSE for children with disabilities. The modifications made is presented below:

The children with disabilities (dyslexic, blind spastic and candidates with visual impairment) have the option of studying one compulsory language as against two. The language opted by them should be in consonance with the overall spirit of the Three Language Formula prescribed by the Board. Besides one language, they can offer any four of the following subjects:

Mathematics, Science and Technology, Social Science, Another Language, Music Painting, Home Science and Introductory Information Technology.

- (h) Restructuring of curriculum for the benefit of students with hearing impairment to facilitate them to take only one language as part of their curriculum.

The Board of Education should make change in their curriculum to facilitate learning of hearing impaired children by providing an option of only one language as a part of their curriculum.

The Government and its organizations dealing with the subject matter of education of children with disabilities shall take immediate action for incorporation of facilities mentioned in Section 30 of the Act so that all the barriers and obstructions may be removed and children with disabilities are able to obtain education at par with other children.

SMT. JAYATI CHANDRA, Jt. Secy.